

- **परभाषा का विस्तार:** बहुमत वाली पीठ ने 2019-2020 में वर्ष 1990 के फैसले को पलट दिया है, जिसमें "मादक शराब" की परभाषा को पीने योग्य शराब तक सीमित कर दिया गया था तथा राज्यों को औद्योगिक शराब पर कर लगाने से रोक दिया गया था।
- **बहुमत की राय:** खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि "नशीली शराब" में सरिफ मादक पेय या पीने योग्य शराब ही शामिल नहीं है। सभी प्रकार की शराब जो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, इस परभाषा के अंतर्गत आती है।
 - न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि शराब, अफीम और नशीली दवाओं जैसे पदार्थों का दुरुपयोग किया जा सकता है तथा फैसला सुनाया कि संसद मादक शराबों पर राज्य की शक्तियों को खत्म नहीं कर सकती है, और कहा कि "नशीली" का अर्थ "जहरीला" भी हो सकता है, जिससे व्यापक वर्गीकरण की अनुमति मिलती है।
- **असहमतपूरण राय:** न्यायमूर्ति बी.वी. नागरतना ने औद्योगिक अल्कोहल के वनियमन के संबंध में बहुमत के फैसले से असहमतवियक्त की और तर्क दिया कि केवल इसलिये कि "औद्योगिक अल्कोहल" का संभावित दुरुपयोग हो सकता है, **प्रवर्षिट 8 - सूची II** को ऐसे "औद्योगिक अल्कोहल" को शामिल करने के लिये नहीं बढ़ाया जा सकता है।
 - राज्यों को औद्योगिक अल्कोहल को वनियमति करने की अनुमति देने से अल्कोहल वनियमन के पीछे वधायी मंशा की गलत व्याख्या हो सकती है।

औद्योगिक अल्कोहल वनियमन पर केंद्र बनाम राज्यों के तर्क:

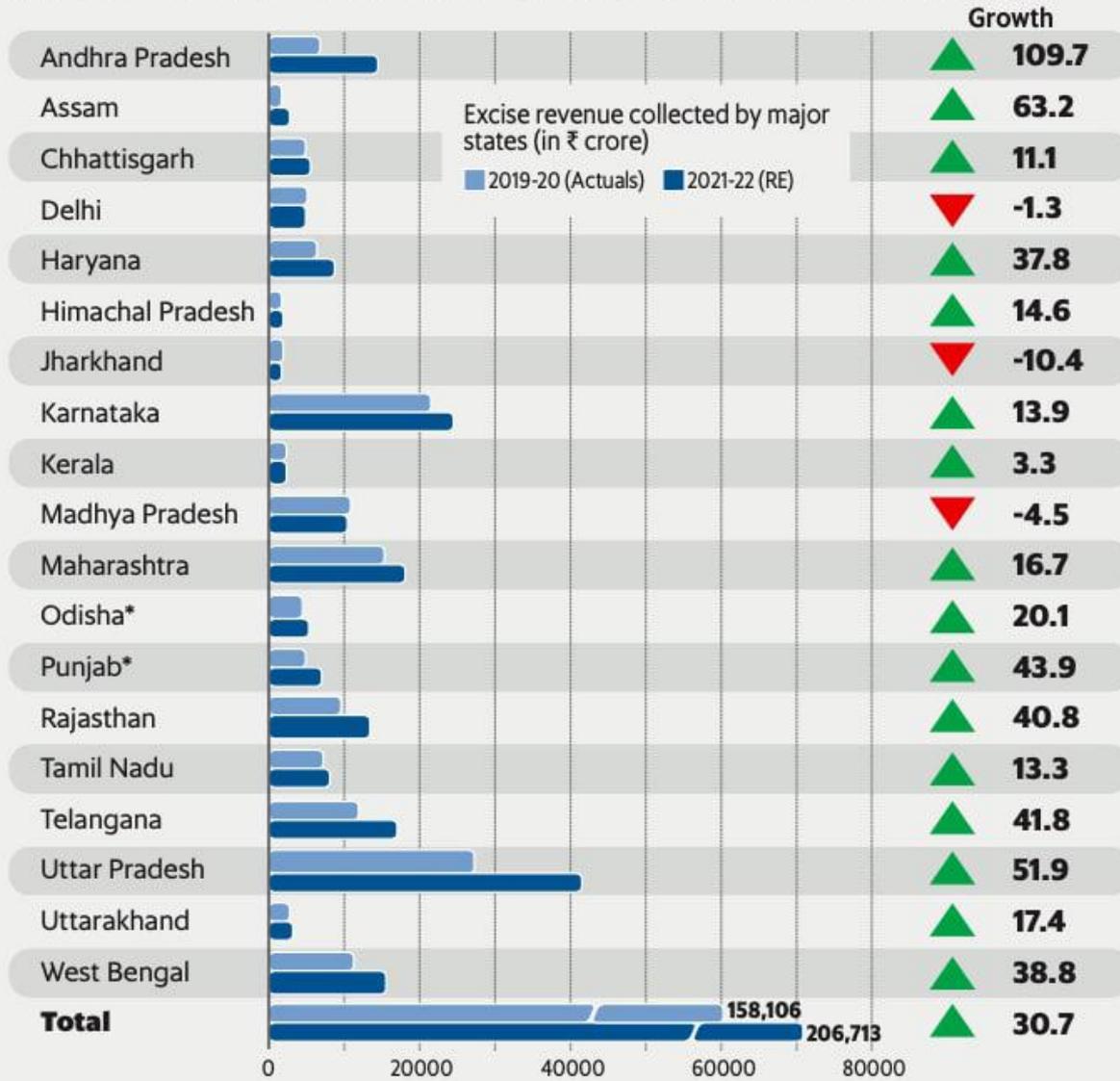
- **केंद्र सरकार का तर्क:**
 - औद्योगिक अल्कोहल को संघ सूची की **प्रवर्षिट 52** के अंतर्गत "उद्योग" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे केंद्र को सार्वजनिक हति में समझे जाने वाले उद्योगों को वनियमति करने की अनुमति मिल गई है।
 - इसमें कहा गया है कि औद्योगिक शराब का व्यापार, वाणज्य, आपूर्ति और वितरण समवर्ती सूची की **प्रवर्षिट 33(A)** के अंतर्गत आते हैं, जो केंद्रीय नगिरानी की अनुमति देता है।
 - केंद्र का कहना है कि औद्योगिक शराब उद्योग (विकास और वनियमन) अधिनियम, 1961 के अधिकार क्षेत्र में आती है, तथा दावा किया कि यह वनियमन के लिये "क्षेत्र पर कब्जा कर लेती है"। इसलिये, राज्य इस वषिय पर अपने नयिमन लागू नहीं कर सकते।
 - केंद्र का तर्क है कि औद्योगिक अल्कोहल ने वनियमन के "क्षेत्र पर अधिकार कर लिया है" जो उद्योग (विकास और वनियमन) अधिनियम, 1961 के अधीन है। इसलिये राज्य इस वषिय पर अपने कानूनों को लागू करने में असमर्थ हैं।
- **राज्यों का तर्क:**
 - राज्य सूची की **प्रवर्षिट 8** के अंतर्गत वनियमन के लिये तर्क देने के साथ मदरि पर कर लगाने के अधिकार पर बल दिया गया, जिसमें औद्योगिक मदरि भी शामिल है।
 - राज्यों द्वारा अवैध उपभोग से नपिटने और राजस्व उत्पन्न करने के लिये प्राधिकार बनाए रखने की आवश्यकता (वशेष रूप से GST के कार्यान्वयन के बाद) है।

राज्यों के लिये शराब पर कर लगाने का महत्त्व

- **राजस्व सृजन:** शराब पर कर लगाना राज्यों के लिये राजस्व का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है। उदाहरण के लिये वर्ष 2023 में कर्नाटक ने भारत नरिमति शराब (IML) पर अतरिकित उत्पाद शुल्क (AED) 20% तक बढ़ा दिया।
- **वत्तीय नरिभरता:** महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्य अपने राजस्व का एक प्रमुख हस्सा शराब करों से प्राप्त करते हैं, जो उनके कुल उत्पाद शुल्क राजस्व का लगभग 30-40% है।
- **लोक सेवाओं का वत्तिपोषण:** शराब पर कर का उपयोग स्वास्थ्य सेवा और शक्तिा सहति आवश्यक लोक सेवाओं के वत्तिपोषण के लिये किया जाता है।

THE GOLDEN GOOSE

Major states collected more than ₹2 trillion under state excise in 2021-22.



*BE figure for 21-22 used as RE figure was not available

Source: RBI, PRS

उद्योग (विकास और वनियमन) अधिनियम, 1951

- उद्योग (विकास और वनियमन) अधिनियम, 1951 भारत में औद्योगिक विकास और वनियमन के लिये वधिक और वैचारिक ढाँचा प्रदान करता है।
- इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य:
 - देश में उद्योगों के विकास को नयित्तरति और नरिदेशति करना,
 - नषिपक्ष संसाधन वतिरण को बढावा देना,
 - आर्थिक शक्ति संकेन्द्रण से बचना,
 - संतुलति एवं नयित्तरति औद्योगिक वसितार को महत्त्व देना।
- यह अधिनियम केन्द्र सरकार को नमिनलखिति शक्तियाँ प्रदान करता है:
 - कुछ उद्योगों के उत्पादन, आपूर्ति और वतिरण को वनियमति करना
 - नये उद्योगों की स्थापना पर प्रतबिध लगाना
 - उद्योगों को संचालन हेतु लाइसेंस प्रदान करना

